पदार्थ हैं । इनमें से कुछ मदों का सिन्टर बनाने में पुन: इस्तेमाल किया जाता है । कोक, कोक ब्रीज और नट कोक जैसी अन्य मदें अन्य उपभोक्ताओं को बेची जा रही हैं ।

"मेल" के इस्पात संयंत्रों में, सामान्य-तया प्रोसेस के दौरान प्राप्त होने वाली मदों को इकट्ठा नहीं किया जाता है । प्रचालनात्मक कारणों से, जहां कहीं मदों का कुछ ढेर लग जाता है, कार्रवाई की जाती है और नियंत्रण के अधीन रखे गए स्टाक समाप्त हो जाते हैं ।

हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड, रांची के लिए पिलेटाइजेशन योजना

354. **श्री अजीत जोगी :**
श्री पृथ्वी मांझी :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड, रांची ने 1972 के आस-पास पिलेटाइजेशन संयंत्र की एक योजना तैयार की थी और उसके निर्माण के लिए अंतर्राष्ट्रीय निविदायें आमंत्रित की गई थी और उन में से एक निविदा को स्वीकृत भी किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो अब इस योजना की प्रगति क्या है ;

(ग) क्या इस योजना को पूर्णतया त्याग दिया गया है ;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) इस योजना पर कुल कितनी राशि खर्च की गई है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री माखन लाल फोतेदार) (क) जी, नहीं ।

(ख) से (ङ) ये प्रश्न नहीं उठते ।

लाख के उत्पादन में कमी

355. **श्री अजीत जोगी :**
श्री पृथ्वी मांझी :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पलाश के वृक्षों में पैदा होने वाले 'लाख' के उत्पादन में भारी कमी आयी है, जिसके परिणामस्वरूप, इस धन्धे में अपना गुजारा करने वाले अनेकों आदिवासियों और मजदूरों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाये गये हैं कि लाख के उत्पादन स्तर में कमी न आए ;

(ग) क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि इसके कारण मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के उमरिया नगर स्थित चपड़ा कारखाने सहित लाख पर आधारित अनेक उद्योग बंद हो गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इन कारखानों को चालू करने की दिशा में कोई पहल की जा रही है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) लाख का उत्पादन 1960-61 में 48000 मीटरी टन के औसत से घटकर इस समय 12000 मीटरी टन रह गया है । इस कमी के कारण इस प्रकार हैं :—

(1) उत्पाद के कम मूल्य ;

(2) मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियां

(3) विदेशों में इसकी मांग में कमी ।

(ख) पांच राज्यों में लाख विकास की एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना शुरू की गई है ।

(ग) मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में उमरिया नगर में स्थित चपड़ा कारखाना मध्य प्रदेश सरकार के वानिकी विभाग द्वारा चलाया जा रहा था। यह कारखाना 1963-64 में बन्द कर दिया गया था, क्योंकि कच्चे माल की कमी थी, उत्पादन कम था और मूल्य भी कम थे।

(घ) इस कारखाने को पुनः चालू करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

Sewer connections to Housing Societies in Pritampura

356. SHRIMATI SUDHA VIJAY JOSHI:

SRRI PAWAN KUMAR BANSAL:

Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a number of Group Housing Co-operative Societies which have been allotted land by the DDA in Pocket No. IV in Pritampura (near Mangolpuri Outer Ring Road) New Delhi, have completed the construction of flats;

(b) if so, whether sewer connections have been given to these colonies; and

(c) if not, by when the sewer connection is proposed to be given so that the occupants may not face inconvenience in the absence of sewer connection?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI DALBIR SINGH): (a) Yes, Sir. 16 Societies have been allotted land and they have nearly completed construction of flats.

(b) No, Sir.

(c) work of laying peripherial sewerage from Outer Ring Road upto Avantika Pumping Station is in progress. Percentage progress of work is about 40 per cent and it is likely to be completed by December, 1989. The outfall pumping station of MCD is also in progress.

Shortage of oilseeds

357. SHRI MUKHTIAR SINGH MALIK: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether there is any shortage of Oilseeds in the country;

(b) if so, the production and consumption of oilseeds at present in the country;

(c) what measures are being taken by Government to meet the shortage of Oilseeds in the country;

(d) whether Government propose to import Oilseeds and if so, the details thereof; and

(e) the foreign exchange reserved for this purpose by Government?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF AGRICULTURAL RESEARCH AND EDUCATION IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI HARI KRISHNA SHASTRI): (a) Yes, Sir. There has been shortage of Oilseeds in the country, resulting in import of edible oil amounting to Rs. 3884 crores during 1981-86.

(b) The country's requirement of edible oil is estimated to be around 54 lakh tonnes. The production of oilseeds in 1988-89 is likely to be 155 lakh tonnes, providing edible oil of the order of 48 lakh tonnes.

(c) Government of India have assisted States with an allocation of Rs. 100 crores during Seventh Plan, under a Rs. 170 crores National Oilseeds Development Project. Rs. 52 crores have been provided in the two years 1987-89 under a special Oilseeds production thurst Project. These funds have been used to support farmers with extension, seeds, bio-fertilizers and plant protection measures etc. in order to increase production of oilseeds